भारत और अमेरिका को व्यापार में आने वाले मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है

लेखक - सी. राजा मोहन (निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

24 सितम्बर, 2019

"भारत और अमेरिका को व्यापार में आने वाले मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह नई दिल्ली को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में गहन बदलाव के लिए तैयार करेगा।"

रविवार को ह्यूस्टन के सम्मेलन में, जहाँ पूरे विश्व ने प्रवासी भारतीयों के उत्साह को देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच की व्यक्तिगत केमिस्ट्री बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन टेक्सास में हुए समारोह के मूल विषय को न्यूयॉर्क में मूर्त रूप देना चाहिए, जहां दोनों नेता आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में फिर से मिलने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी और ट्रम्प पिछले कुछ समय से ठंडे चल रहे व्यापार पर बातचीत को पुनः शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अटकलें दोनों देशों के बीच एक 'छोटे सौदे' के बारे में हैं। फिर भी, दोनों नेताओं को यह भी पता है कि उन्हें सामरिक से परे देखने और द्विपक्षीय वाणिज्यिक जुड़ाव में दिशा बदलने, निकट और मध्यम अवधि के लिए महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य निधारित करने की आवश्यकता है।

कूटनीति में, व्यक्तिगत तालमेल और नेताओं के बीच विश्वास काफी मूल्यवान है। हालाँकि नेता स्वयं समझौतों के विवरण पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने हितों को एक दूसरे से संवाद करने और घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकेत देने की आवश्यकता है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके वार्ताकार की प्राथमिकताओं की पहचान। जब आप दूसरे नेता की सबसे महत्वपूर्ण चिंता को संबोधित करते हैं और उसे जीत का दावा करने के लिए जगह प्रदान करते हैं, तब आपको बदले में बहुत अधिक मिलता है। पिछले दो दशकों में, अमेरिका के साथ भारत के जुड़ाव की सफलता दिल्ली के समझदार फैसलों में निहित है।

हम आसानी से भूल जाते है कि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने मई 2001 में त्वरित एकतरफा समर्थन की पेशकश की थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मिसाइल सुरक्षा का निर्माण करने और परमाणु आतंक के माध्यम से निरोध के सिद्धांत से दूर जाने की पहल की घोषणा की थी। जहाँ उस समय बुश को हथियार नियंत्रण रूढ़िवादिता से उबरने के लिए देश-विदेश में स्तंभित किया जा रहा था, वहीं दिल्ली के समर्थन से वाशिंगटन काफी खुश था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 9/11 के तुरंत बाद बुश को आतंक के लिए मजबूत समर्थन दिया और भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए मंच तैयार किया, जो दशकों से परमाणु मुद्दों पर विवादों से घिरा था।

दिल्ली में अमेरिका की नई राजनीतिक गर्माहट ने बुश को भारत के उत्थान के लिए अभूतपूर्व प्रेरित किया और अमेरिकी घरेलू अप्रसार कानूनों को बदलने के साथ ही भारत के खिलाफ लंबे समय से चल रहे परमाणु अवरोध को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बदलने के लिए एक अनिच्छुक अमेरिकी प्रतिष्ठान का समर्थन किया। हांलाकि, यूपीए सरकार परमाणु समझौते को आगे ले जाने में चूक गयी, लेकिन बुश ने भारत के लिए अपनी मजबूत सहानुभूति बनाए रखी।

परमाणु मुद्दे के समाधान ने अमेरिका के साथ एक उत्पादक साझेदारी का आधार तैयार किया, जिसने अमेरिकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उदारीकरण, आतंकवाद विरोधी सहयोग की शुरूआत, रक्षा संबंधों के विस्तार और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक

सहयोग को आगे बढ़ाया। अगर जसवंत सिंह और वाजपेयी ने यह पहचान करने में सफलता पा ली थी कि बुश के लिए क्या मायने रखता है, तो मोदी ने भी सफलता पा ली थी कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की सर्वोच्च प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना था।

मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दिल्ली की रुकी हुई अंतरराष्ट्रीय वार्ता को भारत की नीति में फिर से लागू किया। एक बार जब बराक ओबामा ने मोदी को जलवायु परिवर्तन के एक भागीदार के रूप में देखा, तो उन्होंने परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में मदद की और भारत को वैश्विक अप्रसार व्यवस्था में एकीकृत किया।

परमाणु मुद्दे के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर, दो अलग-अलग तिमाहियों से भारतीय प्रणाली के भीतर मजबूत प्रतिरोध था, जिनमें कुछ दोष ढूँढ़ने वाले और कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो अमेरिका के साथ हर जुड़ाव को भारत के गैर-सरेखण की सर्वोच्च परीक्षा के रूप में देखते थे। दोष ढूँढ़ने वाले ज्यादातर नौकरशाही से थे जिन्होंने भारत को होने वाले बड़े लाभ को देखने से साफ इंकार कर दिया था। राजनीतिक वर्ग ने भारत के लंबे समय से चली आ रही बातचीत में किसी भी तरह के बदलाव की घोर निंदा की।

जब ट्रम्प ने जनवरी 2017 में व्हाइट हाउस का कार्यभार संभाला था, तो मोदी और उनके सलाहकारों ने इस बात को परखने में देर नहीं की। राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्तियों से बहुत अलग होंगे और वे कई दीर्घकालिक अमेरिकी नीतियों को बदलने भी जा रहे थे। हांलाकि, शुरुआत में मोदी ने व्यापार के मोर्चे पर उभरती चुनौतियों के लिए पर्याप्त राजनीतिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दोष ढूँढ़ने वालों को व्यापार वार्ता का नेतृत्व करने दिया। हाल के वर्षों में उदारीकरण के व्यापार के प्रति भारत के अभिमानी रवैये ने इसे अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ संकट में डाल दिया। इसके बाद इनमें से अधिकांश ने भारत का साथ छोड़ दिया और ट्रम्प ने इसे फसाद की जड़ बना दिया। भारत-अमेरिका संबंधों पर अपने भाषण में, ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि भारत के लोगों को 'संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित सुंदर वाक्यांश के साथ मुद्रांकित उत्पादों तक पहुंच' होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें, तो बाजार पहुंच वह मुद्दा रहा है जिसने हाल के वर्षों में देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुँचाया है।

पीएम इस बात से अवगत हैं कि ट्रम्प के साथ एक व्यापार समझौते में कटौती करने से आतंकवाद, कश्मीर और अफगानिस्तान में संकट सहित कई मुद्दों पर अपने प्रशासन से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता केवल मोदी और ट्रम्प के बीच तत्काल आदान-प्रदान के बारे में नहीं है।

ट्रम्प की राजनीति के साथ ही साथ तकनीकी व्यवधान के कारण, वैश्विक आर्थिक क्रम में गहन बदलाव के लिए भारत को तैयार करने के बारे में एक नया व्यापार समझौता होना चाहिए। भारत के संबंध में ट्रम्प की कई व्यापारिक चिंताएं डेमोक्रेटिक पार्टी के बाएं विंग के साथ संबंधित हैं। निकट अवधि में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध सही होना और दीर्घकालिक रूप से अमेरिका के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यावसायिक साझेदारी के लिए एक साहसिक कोर्स करना अपने आप में आवश्यक और योग्य लक्ष्य हैं।

GS World
Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **वर्तमान में भारत एवं अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर विचार कीजिए-**

   1. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कटौती करने से आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा जैसे कई पहलुओं से निपटना बहुत आसान हो जाएगा।
   2. वैश्विक आर्थिक क्रम में बदलाव को देखते हुए भारत को अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता करना चाहिए।
   3. भारत और अमेरिका के नये समझौते से भारत वर्तमान आर्थिक मंदी से बाहर निकल पायेगा।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 3 (b) 2 और 3

   (c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the present business relations of India and America.**

   1. Reducing trade agreement with US will make it very easy to deal with many aspects like terrorism, Kashmir issue.
   2. Viewing the change in global economic order, India should enter into a new trade agreement with America.
   3. India could get out of the current economic slowdown with the help of new agreement between India and America.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 3 (b) 2 and 3

   (c) 1 and 2 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत-अमेरिका संबंध सामरिक, कूटनीतिक मुद्दों को लेकर बेहतर होते जा रहे हैं, किन्तु व्यापार को लेकर अभी दोनों देशों के मध्य कई असहमतियां विद्यमान हैं।' दोनों देशों के मध्य व्यापार में मौजूद बाधाओं की चर्चा कीजिए तथा इनके समाधान हेतु कौन-से कदम उठाने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

Q. 'Indo-US relations are getting better on strategic, diplomatic issues, but there are many disagreements between the two countries regarding trade.' Discuss the obstacles in trade between the two countries and what steps need to be taken?

(250 Words)

नोट : 23 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।